In the meantime, BIFR has appointed the Indusrial Credit and Investment Corportion of India Limited (ICICI) as the Operating Agency on 16-3-1994, directing the Government to submit the unit wise revival package to ICICI which in turn would submit a rehabilitation plan to BIFR. Any decision on the revival of these companies would depend on the outcome of the proceedings pending before the BIFR which is a quasi-judicial authority.

हिमाचल प्रदेश में भूकम्प वेधशालाओं का बंद किया जाना

*647. **श्री महेश्वर सिंह :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 मार्च, 1994 की स्थिति के अनुसार भूकम्प वैधशालायें कहां-कहां कार्यरत हैं और वे कब-कब से कार्यरत हैं –

(ख) इन वेधशालाओं के खोलने का औचित्य क्या था और वे वैधशालायें क्या-क्या कार्य कर रही हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर भारत में हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र, जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों को भूकम्पीय क्षेत्र माना जाता है ; और

(घ) यदि हां, तो हिमाचल प्रदेश में कुल्लू तथा धर्मशाला की भूकम्पीय वैधशालाओं को किन-किन कारणों से बन्द कर दिया गया है और निकट भविष्य में हिमाचल प्रदेश में स्थित ऐसी छः अन्य वैधशालाओं को बन्द करने का निर्णय किन कारणों से लिया गया है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष विभागों तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) :

(क) भारत मौसम विज्ञान विभाग देश में अपने राष्ट्रीय नेटवर्क में 37 भूकम्पीय वेधशालायें चला रहा है । कलकत्ता के अलीपुर में पहली वेधशाला की सन 1898 में स्थापना से लेकर आज तक इस नेटवर्क का धीरे-धीरे विस्तार किया जिसमें सबसे नवीन स्थापना 1993 में लातूर में की गई । इसके अलावा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने अपने भूकम्पीयता कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर पश्चिमी हिमाचल में 39 वेधशालायें स्थापित की जिनमें हिमाचल प्रदेश की 12 वेधशालायें शामिल हैं जिनकी स्थापना सन 1984 से शुरू की गई । वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र भी उत्तर पूर्वी क्षेत्र एवं दक्कन के पठार में भूकम्पीय केन्द्र चलाते हैं ।

(ख) ये वेधशालायें भारत तथा इसके आस-पास के इलाकों की भूकम्पीय गतिविधियों की मानीटरिंग करती हैं । इन वेधशालाओं द्वारा जो आंकड़े उपलब्ध होते हैं उनका प्रयोग विभिन्न वैज्ञानिक एवं विकासात्मक गतिविधियों में किया जाता है ।

(ग) जी, हां, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश की पहाड़ियों, जम्मू और कश्मीर तथा उत्तर पूर्वी राज्य वैसे ज्ञात भूकम्पीय जोनों में स्थित हैं जैसा कि ब्यूरो आफ इंडियन स्टैंडर्स के जोनिंग मैप 15: 1993–94 में दिखाया गया है ।

(घ) भारत मौसम विज्ञान विभाग तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने अपनी कोई वेधशाला बन्द नहीं की है । कुल्लू तथा धर्मशाला स्थित वेधशालाएं जिन्हें भारत मौसम विभाग भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड की ओर से संचालित करता है, बोर्ड के विशेष आग्रह पर बन्द कर दिया गया है । भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा हिमाचल प्रदेश की 6 अन्य वेधशालाओं को बन्द करने के बारे में कोई कदम नहीं उठाया गया है । बोर्ड के कुल्लू तथा धर्मशाला स्थित वेधशालाओं के बन्द होने की वजह से

हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र के भूकम्पीय मानीटरिंग के मुख्य उद्देश्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की भूकम्पीयता कार्यक्रम के तहत हिमाचल प्रदेश में स्थापित 13 वेधशालायें एवं एक स्ट्रोंग मोशन एक्सेलरोग्राफ एरे (50 यंत्र) उपलब्ध है।

Air Services on different routes

*648. SHRI RAHASBIHARI BARIK: Will the Minister of CIVIL AVIATION AND TOURISM be pleased to state:

(a) whether there have been growing demands for providing adequate air services on Delhi-Bhubaneshwar-Port-Blair route. Delhi-Calcutta-Bhubaneshwar route, Delhi-Bombay-Bhubaneshwar route; and Delhi-Madras-Bhubaneshwar route, and

(b) if so, the details of steps taken to fulfil those demands?

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION AND TOURISM (SHRI GHULAM NABI AZAD): (a) Indian Airlines has received requests to operate Delhi-Bhubaneshwar-Port-Blair service and also to connect Bombay with Bhubaneshwar.

(b) At present, Bhubaneshwar is connected by direct services with Delhi, Calcutta, Madras, Hyderabad and Nagpur. Due to operational and commercial reasons. Indian Airlines is not in a position to connect Bhubneshwar with any more places or to increase frequency of any of the existing flights.

Draught animal power

*649. SHRI SARADA MOHANTY:

SHRI SOM PAL:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether a two-day national conference on draught animal power recently organised in New Delhi high lighted the important role of this source of energy in our economy;

(b) if so, what are the major views and recommendations; that have emerged out of the deliberations;

(c) whether some experts have suggested measures including enactment of laws and adopting a breeding policy to conserve and augment the indigenous breeds of such cattle;

(d) if so, what steps Government are taking in this regard;

(e) whether Government have on its own, made some studies to assess the contribution of draught animals to our energy needs at present and in future; and

(f) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (SHRI S. KRISHNA KUMAR): (a) Yes, Sir, a National Conference was organised on Modernisation of the Draught Animal Power (DAP) Systems on 4th and 5th March, 1994 in New Delhi.

(b) The Major views and recommendations that have emerged from the National Conference are:

(i) Top-most priority to be given for DAP in the country's economic and development programmes,

(ii) Higher level of utilisation of DAP through diversification programmes like use of water lifting, power generation etc.,

(iii) Higher allocation of DAP Programme in Central and State Budgets by the Planning Commission and linkage with other rural development and social upliftment programmes of the Government.